VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1835)

Name of Candidate	Pooja Meena		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	154350
Center	online	Date	18/8/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India threatens the spirit of cooperative federalism in India. Discuss. (150 words) 10

भारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेना भारत में सहकारी संघवाद की भावना के लिए खतरा उत्पन्न करता है। चर्चा कीजिए।

सी. बी. आई को सामान्य सहमति देकर राज्य सरकार, राज्य में सी. बी. आई को निरीक्षण संबंधित असीमित शक्तियाँ निश्चित समयावधि के लिए प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र द्वारा इसे वापस ले लिया गया।

सहकारी संघवाद के समक्ष खतरा

→ सहकारी संघवाद के माध्यम से केन्द्र व राज्य पारस्परिक सहमति से राष्ट्रीय सुरक्षा व अखंडता को सुनिश्चित करती है।

→ संघवाद के 'शक्तियों के विभाजन' सिद्धांत के विरुद्ध

→ सी. बी. आई द्वारा राज्य के किसी अधिकारी पर कार्यवाई करने की शक्ति को सीमित करता है।

→ सी. बी. आई, संघवाद का प्रतीक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपर्युक्त बिन्दु सिर्फ एक पक्षीय दृष्टिकोण है। 1967 के बाद से भारत के शासन व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हो गया है।

केन्द्र व राज्य में भिन्न-भिन्न सरकारों के चलते सी.बी.आई., ई.डी का राज्य के प्रशासन को क्षीण करने हेतु भी प्रयोग किया जाता है जो कि एकात्मक व्यवस्था का द्योतक है।

विधि आयोग की रिपोर्ट में एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के गठन की सिफारिश की, जो इस प्रकार के मुद्दों को सुलझाएँ।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Stating the sources of finance for local self-governments in India, suggest ways to strengthen their financial position. (150 words) 10

भारत में स्थानीय स्व-शासी सरकारों के लिए वित्त के स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय सुझाइए।

73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन अधिनि. द्वारा भारतीय संविधान में 'स्थानीय सरकारों' का गठन किया गया है। अनुच्छेद - 243 'आई' 'राज्य वित्त आयोग' से संबंधित है।

वित्त के स्रोत

→ स्थानीय निकायों को अनुच्छेद -243'I' के तहत राजस्व का आवंटन राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के मध्य किया जाता है।
→ केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान से
→ केन्द्र प्रायोजित एवं केन्द्रीय क्षेत्रक योजना से प्राप्त धन राशि
→ पद्रंवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति अत्यंत दयनीय है / राज्य सरकारों की भाँति स्थानीय निकायों को कराधान की शक्तियाँ नहीं होती। वित्त हेतु प्रणाली राज्य व केन्द्र पर निर्भर होते है।

वित्तीय स्थिति को मजबूत करने उपाय

- राज्य वित्त आयोगों का समय-समय पर गठन
- ग्राम पंचायतों की भाँति अन्य निकायों को कराधान शक्तियाँ प्रदान करना।
- राज्य से कराधान की शक्तियाँ स्थानीय निकायों को हस्तांतरित

वित्तीय सुदृढता प्रदान कर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं गांधीजी के 'स्वराज' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Cabinet Committees play an important role in reinstating collective responsibility and principle of homogeneity of the Executive in the Indian Parliamentary system. Elucidate. (150 words) 10

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पष्ट कीजिए।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ गैर-संवैधानिक प्रकृति की है। वर्तमान में 8 मंत्रिमंडलीय समितियाँ है।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ
- राजनीतिक मामलों
- संसदीय आवास संबंधी
- गृह मामलों संबंधी
- रक्षा संबंधी
- नियुक्ति संबंधी
- निवेश संबंधी
- कौशल एवं विकास संबंधी

संसदीय मामलों एवं नियुक्ति संबंधी को छोड़कर सभी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित
- लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
- संसदीय प्रणाली के अनुरूप
- कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति
- सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ-साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ-साथ व्यापक कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करती है।

कार्यपालिका की एकरूपता

→ कैबिनेट के ही मंत्री मंत्रिमंडलीय समितियों में प्रतिभागी हो सकते हैं।

→ गैर-कैबिनेट मंत्रियों को समितियों की कार्यवाही में भाग लेने से निषेध।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ तीव्र एवं समरूप निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करती है।

4. There is a need to overhaul the public procurement and project management (PPPM) framework of India for faster, efficient and transparent execution of government projects. Comment.

(150 words) 10

सरकारी परियोजनाओं के तीव्र, कुशल और पारदर्शी निष्पादन के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन ढांचे की सहायता से सरकारी परियोजनाओं का प्रबंधन किया जाता है।

सा. ख. प. प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ

- क्रॉनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। सार्वजनिक खरीद करते समय निजी हितों की पूर्ति हेतु ऑक्शन में घपला करना
- नीलामी संबंधी दिशा-निर्देशों एवं नियमों के निर्माण में सभी हितधारकों को शामिल नहीं करना
- राजनेताओं द्वारा नजदीकी रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना।
- खराब निर्माण सामग्री का प्रयोग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखो)

सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार

↓

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता से नीलामी, खरीद एवं अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों का सम्पादन।
- तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से निरीक्षण एवं निगरानी तंत्र का गठन।
- जनता को निर्माण सामग्री संबंधी जानकारी सार्वजनिक करना।

उपर्युक्त कदमों की सहायता से परियोजनाओं का तीव्र, कुशल और पारदर्शी निष्पादन संभव होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Adequate measures are required to overcome the challenges and vulnerabilities associated with undertaking social accountability initiatives and institutionalising them. Elaborate. (150 words) 10

सामाजिक जवाबदेही पहलों की शुरू करने और उन्हें संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपायों की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

सामाजिक संस्थानों एवं जनता के प्रति जवाबदेहता, सामाजिक जवाबदेही कहलाती है। इसके अंतर्गत सूचना का अधिकार अधि०, नागरिक चार्टर इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

सामाजिक जवाबदेही से संबंधित चुनौतियाँ

निर्माण / शुरू

- जनता को निर्माण के समय शामिल न करना
- उचित प्रारूप एवं रोडमैप का अभाव
- विधायी ढाँचे का अभाव होना।

संस्थागत बनाने

- जनता में जागरूकता का अभाव
- निगरानी व निरीक्षण तंत्र का अभाव
- कार्यान्वयन तंत्र का अभाव

- निरंतर व आवधिक मूल्यांकन का अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(पर्याप्त उपाय)

→ निर्माण के समय क्षमता एवं सम्मिलित हितधारकों को सम्मिलित करना। (जैसे → नागरिक घोषणा पत्र एवं सूचना अधिकार में)

→ पारदर्शी तंत्र का गठन करना।

→ क्षमता निर्माण; कुशल एवं प्रभावी कर्मचारियों की नियुक्ति

→ स्थानीय हितों एवं भाषा से जुडी हुई।

मेघालय द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण ~~से~~ संबंधी अधिनियम के माध्यम से सामाजिक जवाबदेही का उत्कृष्ट नमूना पेश किया गया।

6. In view of the recent Parliamentary Standing Committee report, discuss the issues faced by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) and suggest measures that can be adopted to strengthen it. (150 words) 10

एक संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए और इसे मजबूत बनाने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

संविधान के अनुच्छेद - 338'क' में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संबंधी प्रावधान है।

प्रमुख कार्य
- शिकायतों को प्राप्त करना
- शिकायतों की जांच व कार्यवाही
- मानवाधिकारों की रक्षा
- दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ

सामना की जाने वाले मुद्दे
(संसदीय स्थायी समिति)

→ ~~रख~~
→ अधिकांश आदिवासी जनता दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, शिकायत हेतु पहुँच का अभाव।

→ अधिकतर आदिवासी असाक्षर एवं अजागरूक, जिसके चलते शिकायत

दर्ज नहीं हो पाती।

→ उचित मशीनरी एवं कर्मियों का अभाव

→ आयोग के पास सिर्फ परामर्शकारी शक्तियाँ

मजबूत बनाने के उपाय

↓

→ आयोग को आपराधिक शक्तियाँ भी प्रदान की जानी चाहिए।

→ आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी बनाई जाए।

→ जनता की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रों की स्थापना

भारत की लगभग 9% जनसंख्या आदिवासी जनसंख्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सुदृढ़ता प्रदान करना समय की मांग है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. While the Mid-Day Meal scheme was aimed at fulfilling the nutritional needs of students, it is far behind in achieving this objective. Discuss. Also, suggest remedial measures in this context. (150 words) 10

यद्यपि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था, किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह काफी पीछे है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने एवं विद्यालयों में सकल नामांकन बढ़ाने हेतु 'मिड-डे मील' योजना का शुभारंभ किया गया।

योजना संबंधी चुनौतियाँ

- विद्यालय में सकल नामांकन में वृद्धि प्राथमिक लक्ष्य हो गया, पोषण पूर्ति के बजाय।
- वित्तीय आवंटन की कमी → शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5-3% तक ही व्यय किया जाता है।
- शिक्षकों को ही योजना का कार्य सौंपा जाना।
- न्यूट्रीशियन विशेषज्ञ के बिना ही डाइट चार्ट का निर्धारण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपर्युक्त चुनौतियों को देखते हुए हाल ही में मिड डे मील का नाम बदलकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण शक्ति अभियान कर दिया गया है।

उपचारात्मक उपायों का उल्लेख

- खाद्य पर्याप्तता के साथ खाद्य पोषणता पर ध्यान केन्द्रित
- पोषण वाली तत्वों यथा मोटे अनाज क्षेत्रीय अनुरूप दालें एवं खाद्य सामग्री सम्मिलित की जाएगी।
- पोषण संबंधी विशेषज्ञ की नियुक्ति
- शिक्षकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार 2041 तक जनसांख्यिकी लाभांश चरम पर होगा, जिसके लिए आज की पीढ़ी को कल के लिए तैयार करना होगा।

8. Sexual and reproductive health and rights (SRHR) remain critical for the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, discuss the impediments in the fulfilment of SRHR in India. Also, mention the steps that can be taken in this regard. (150 words) 10

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, भारत में SRHR की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के अन्तर्गत विवाह करने, माँ बनने, गर्भ-निरोधकों का प्रयोग एवं परिवार नियोजन पद्धतियों का प्रयोग करने संबंधी अधिकारों को शामिल किया जाता है।

भारत में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार की स्थिति पर दृष्टि

- विश्व की हर तीसरी विधवा भारत में
- विश्व की सबसे ज्यादा बाल वधू भारत में
- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में निम्न स्तर
- मातृ मृत्यु दर – 122, एनीमिया
- समलैंगिकों एवं ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों की अवहेलना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ मत लिखें)

भारत में प्रमुख बाधाएँ

- **सामाजिक**
  - पितृसत्तात्मक सोच
  - महिला को निम्न समझना
- **कानूनी**
  - कानूनों का अपूर्ण क्रियान्वयन
  - महिलाओं के विरुद्ध सशक्त कानूनों का अभाव
- **आर्थिक**
  - अवैतनिक कार्यों में संलिप्तता
  - समान कार्य हेतु समान वेतन ना
- **स्वास्थ्य**
  - खराब महिला स्वास्थ्य
  - मातृ मृत्यु दर
  - संस्थागत प्रसव
- **राजनीतिक**
  - राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव

उठाए जा सकने वाले कदम

- बाल विवाह रोकने हेतु "विवाह की आयु को 21 वर्ष करना"
- साक्षरता अभियान → स्वयं, स्वयंप्रभा (साक्षरता व स्वास्थ्य पूरक)
- चिकित्सीय स्तर पर → संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित, (जननी सुरक्षा योजना)

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. State the functions of the United Nations Human Rights Council. Also, discuss the issues faced by the Council in the promotion and protection of human rights around the globe. (150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण में परिषद द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया। यह यू.एन की प्रमुख एजेंसियों में से एक है।

मानवाधिकार परिषद के प्रमुख कार्य

- विश्व के सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना।
- मानवाधिकारों की रक्षा हेतु चार्टर का निर्माण एवं घोषणा।
- मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में कार्यवाई करना
- यू.एन परिषद में मुद्दे को चर्चा के लिए भेजना एवं सहमति लेना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

[परिषद द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे]

→ मानवाधिकारों की स्पष्ट परिभाषा का अभाव

→ तालिबान, इराक का मोहसुल इत्यादि मुद्दों पर मौन रहना, इसकी साख पर प्रश्न उठाता है।

→ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सदस्यों में से नियुक्ति (सदस्यों की अफ्रीका एवं एशिया के कई देश) सदस्य नहीं

यू.एन. मानवाधिकार परिषद तटस्थ एवं निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही है। अतः समावेशी एवं "वसुधैव कुटुम्बकम" को प्राप्त करने हेतु इसे निष्पक्ष बनाना आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. West Asia is an important strategic region for India with profound geo-political and geo-economic significance. Discuss. (150 words) 10
अत्यधिक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व के कारण पश्चिम एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। चर्चा कीजिए।

पश्चिम-एशिया या मध्य-पूर्व, अफ्रीका एशिया एवं यूरोप के तिराहे पर अवस्थित है।

पश्चिम एशिया - भारत के लिए महत्व

① भू-राजनीतिक महत्व

→ भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। (ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की आपूर्ति)

→ 'डि-हाइफनेशन नीति' से इजराइल और फिलीस्तीन के साथ राजनीतिक संबंधों में सहायक

→ एशिया में शक्तिशाली रूप एवं चीन को प्रतिसंतुलित करने हेतु आवश्यक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(c) भू-आर्थिक महत्व

→ भारत सऊदी-अरब अमीरात एवं ईरान से तेल आयात करता है।

→ तापी परियोजना से गैस की आपूर्ति (तुर्कमेनिस्तान - अफगानिस्तान - पाकिस्तान एवं भारत)

→ आर्थिक - व्यापार एवं बहुपक्षीय समझौतों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु

हाल ही में किया गया I2U2 (इंडिया - इजराइल, यूएसए - यूएई) वैश्विक पटल पर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की नई तस्वीर पेश करेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Disenfranchising prisoners desecrates a cherished value in a democracy i.e. 'right to vote', which should be guarded earnestly. Discuss in the light of The Representation of The People Act, 1951. (250 words) 15

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के एक प्रशंसनीय मूल्य, अर्थात् "मतदान के अधिकार" का अपमान करना है, जिसकी गंभीरतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बिना किसी भेदभाव के मतदान के अधिकार को वर्णित किया गया है।

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के प्रशंसनीय मूल्य "मतदान के अधिकार" का अपमान करना है। इस अधिकार की गंभीरता पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए।

मताधिकार देना क्यों आवश्यक

© लोकतांत्रिक आदर्श; जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन को बनाए रखने हेतु।

© संसदीय एवं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की स्थापना हेतु एक पूर्वमान्यता के रूप में शुरू किया जाना चाहिए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के राजनीतिक दलों की मान्यता, प्रतिनिधियों से संबंधित अर्हताओं एवं निरर्हताओं का वर्णन किया गया है।

कैदियों को मताधिकार नहीं देने के पक्ष में तर्क →

→ लोक प्रति० अधिनियम किसी अपराध में आरोपी पाए जाने पर यदि 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है तो कैदियों को भी मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

→ कैदियों द्वारा लोक-लुभावन में आकर मत देना या किसी राजनीतिक दल द्वारा मत को खरीद लेना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कैदियों को मताधिकार होने से मत का मूल्य समाप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे न केवल लोकतंत्र का ह्रास होगा अपितु राजनीतिक अपराधीकरण भी बढ़ेगा।

विधि आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि मत का अधिकार मौलिक अधिकारों के समान ही है। अतः उचित निगरानी व देखरेख में इसका निष्पादन किया जाना चाहिए।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. There are similarities and interactions between the affirmative action adopted by India and USA owing to similar historical injustices faced by their respective vulnerable groups. Discuss. (250 words) 15

भारत और यू. एस. ए. के सुभेद्य समूहों द्वारा सामना किए गए एकसमान ऐतिहासिक अन्याय के कारण, इनके द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के बीच समानताएं हैं और इनका एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। चर्चा कीजिए।

ऐतिहासिक कारणों से पीड़ित समुदायों को विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही का प्रयोग कर संरक्षणात्मक भेदभाव किया जाता है। जैसे - आरक्षण, प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

भारत और यू.एस.ए के सुभेद्य समूहों में महिलाएँ, वंचित वर्ग के समुदाय यथा दलित, आदिवासी अश्वेत, दिव्यांग एवं वृद्धों को शामिल किया जा सकता है। दोनों ने इन समुदायों पर ऐतिहासिक अन्याय के कारण सकारात्मक कार्यवाई का प्रावधान किया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों एवं अन्य प्रावधानों के माध्यम से जैसे अनुच्छेद 15, 16, 330, 332, 243 कार्यवाहि के माध्यम से शिक्षा, रोजगार एवं राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

अमेरिका में 15% अश्वेतों के साथ समानता स्थापित करने हेतु समान प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

दोनों की कार्यवाहियों में समानता

① दोनों देशों द्वारा मानवाधिकारों के आधार पर मौलिक अधिकारों को अपनाया है।

② दोनों देशों ने समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण, मानक पद्धतियों का प्रयोग किया है।

(ग) दोनों देशों द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को स्वीकारा। उसी का परिणाम रहा कि देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तथा अमेरिका को प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति 'बराक ओबामा' प्राप्त हुए

सकारात्मक कार्यवाही के प्रभाव

↓

भारत और अमेरिका द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्यवाही का इनके ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्रीय व राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए योगदान। अमेरिका की ~~तत्कालीन~~ वर्तमान उपराष्ट्रपति 'कमला हैरिस' का चुनना सकारात्मक कार्यवाही का परिणाम है।

सकारात्मक कार्यवाही पुरस्कार का नहीं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है।

13. Objections to domicile-based reservation in private sector jobs on the grounds of constitutional equality and freedom are misplaced. Critically discuss. (250 words) 15

संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति अनुचित है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

हाल ही में तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र, पंजाब में निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण की बात चर्चा में रही।

निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण देने पर आपत्ति

- स्वतन्त्रता एवं समानता के अधिकार के विरुद्ध; अनुच्छेद 14 व 15 में किसी लिंग, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है।
- राष्ट्रीय एकता व अखंडता के विरुद्ध
- अनुच्छेद-16 में वर्णित नियोजन में जन्म, वंश, लिंग, जाति एवं निवास स्थान के स्थान पर भेदभाव का निषेध किया गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- स्थानीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के मध्य टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है।

निजी क्षेत्र की नौकरियों में निवास आधारित आरक्षण (पक्ष में तर्क)

① प्रवासन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी

② मानवोचित आजीविका एवं रहन-सहन की स्थितियाँ प्रदान (अनुच्छेद 21 'प्राण व दैहिक स्वतंत्रता) के अनुकूल

③ संवैधानिक समानता के अनुकूल माना जा सकता है / क्षेत्रीय हितों को समान अवसर प्रदान करके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपर्युक्त मुद्दा सकारात्मक एवं नकारात्मक समानता के विचारधारा से संबंधित है। एक में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों के अभाव की बात कही गई है। दूसरे में समान के साथ असमान के साथ असमान व्यवहार को समर्थन किया गया है।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

14. There have been arguments that sedition law is an attack on the very foundation of India's liberal democratic principles, as enshrined in the Constitution. Do you agree? (250 words) 15
ऐसा तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह कानून भारत के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला है, जैसा कि संविधान में निहित हैं। क्या आप सहमत हैं?

आईपीसी की धारा 124A के तहत 'राजद्रोह कानून' औपनिवेशिक काल का कानून है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे आदर्शों की मान्यता है। इन आदर्शों के साथ राजद्रोह कानून विरोधाभास पैदा करता है।

राजद्रोह कानून के पक्ष में तर्क

- राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता हेतु राजद्रोह कानून का होना आवश्यक
- आतंकवादी गतिविधियों, आपातकालीन बाह्य एवं आंतरिक असामाजिक गतिविधियों से रक्षा हेतु)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑦ केदारनाथ वाद एवं कन्हैया कुमार वाद में राजद्रोह कानून को सीमित रूप से स्वीकारा गया है।

राजद्रोह कानून के विपक्ष में तर्क

① मौलिक अधिकार वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विरुद्ध साथ अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत मानवीय गरिमा का हनन।

② विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विद्यमान विधि/कानून व्यवस्था को बनाए रखने के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

③ औपनिवेशिक विरासत का नमूना। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा स्वतन्त्रता आंदोलन को रोकने हेतु प्रयोग का उपकरण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान की राजद्रोह कानून की स्थिति पर दृष्टि डालें तो इसमें दोषी मामलों में सिर्फ 1-2% के ही मामले उचित ठहराए जाते हैं। अतः प्रामाणिकता के आधार पर भी स्वीकार्य नहीं।

विधि आयोग की 176वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की सुरक्षा एवं अखंडता को ठेस पहुँचाने वाली एवं कानून व्यवस्था का हनन करने वाली गतिविधियों पर राजद्रोह कानून का यथोचित प्रयोग किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Despite Government e-Marketplace facing certain challenges, it has brought about a significant improvement in the procurement of goods and services by various government agencies. Discuss. (250 words) 15

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, इन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण सुधार किया है। चर्चा कीजिए।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- ऑनलाइन निरीक्षण का अभाव; जिसके चलते असंगत गतिविधियाँ उत्पन्न होने का भय।
- उपयुक्त अवसंरचनात्मक ढाँचे का अभाव; तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी बाध्यताएँ, नेटवर्क स्पीड को लेकर अवरोध। उदा- दिल्ली जैसे शहर में नेटवर्क की धीमी गति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⊙ सक्षम एवं तकनीकी प्रवण कर्मचारियों का अभाव

⊙ अंतर संस्थागत समन्वय का अभाव (विभागों एवं मंत्रालयों के मध्य)

उपर्युक्त सभी मुद्दों को देखते हुए सरकार द्वारा Indea करके नई पहल शुरुआत की गई।

महत्वपूर्ण सुधार
↓

→ अवसंरचनात्मक ढांचे में सुधार किया गया; तकनीकी एवं प्रौद्यो. अवसंरचना का विकास; कम्प्यूटर एवं ब्रॉडबैंड की पहुँच

→ नेटवर्क की गति को बढ़ाने हेतु तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम

→ वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुँच

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को सूचारु बनाना)

→ 25% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से खरीदना अनिवार्य बनाया गया, जिसमें महिलाओं का एक निश्चित अनुपात निर्धारित किया।

→ कॉर्नी कैपिटलिज्म समाप्त करने के प्रयास

→ अंतर-संस्थागत समन्वय एवं क्षमता निर्माण

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की सहायता से सरकारी एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान की जा सकती है।

Don't write anything in margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. A reformed system of recruitment, training and evaluation needs to be put in place to take forward the development of a highly efficient and accountable civil service. Discuss in the context of India. **(250 words) 15**

अत्यधिक कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की एक संशोधित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

स्वतन्त्रता पूर्व से ही सिविल सेवा अस्तित्व में है। स्वतन्त्रता के बाद सिविल सेवकों की भूमिका अत्यन्त व्यापक एवं सामाजिक - आर्थिक विकास की स्थापना करनी हो गई है।

वर्तमान में सिविल सेवा में निम्न समस्याएँ हैं →

→ औपनिवेशिक विरासत को अपनाए हुए

→ रोल बेस्ड न होकर रूल बेस्ड (नियमों व प्रक्रिया का हवाला)

→ राजनीति का नौकरशाहीकरण जिसके चलते राजनीति-अपराधीकरण में वृद्धि

→ जनता के प्रति सेवक नहीं प्रशासक का भाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिविल सेवा में निम्न चरणों पर परिवर्तन

भर्ती → वर्तमान में तीन चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस प्रक्रिया से पूर्ण आकलन संभव नहीं हो पाती। अतः बासवान एवं होता समिति की अनुशंसा को मानना।

प्रशिक्षण → वर्तमान में 2 वर्ष का संस्थान + फील्ड उन्मुख प्रशिक्षण मसूरी के केन्द्र पर दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक एवं सर्वांगीण नैतिक विकास हेतु पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता

बासवान समिति ने प्रशिक्षण के परफॉर्मेंस बेस पर काडर का आवंटन की सिफारिश।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मूल्यांकन → 360° मूल्यांकन, प्रशिक्षण के दौरान, कार्य के दौरान, आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

वर्तमान में निरंतर एवं आवधिक मूल्यांकन का अभाव देखने को मिलता है।

प्रमुख सिफारिशें

→ नौकरशाही के आकार में कमी
→ अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष करना
→ पार्श्व प्रवेश का समर्थन
→ विशेषज्ञों की आवश्यकता

डॉ. पटेल द्वारा सिविल सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी। अतः इनकी भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

17. Despite initiatives taken by the Indian government to achieve critical goals in the education sector, major interventions are required to tackle learning poverty as well as the persisting inequalities. Discuss. (250 words) 15
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों के बावजूद, लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) के साथ-साथ विद्यमान असमानताओं से निपटने के लिए बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

हाल ही में एनजीओ 'प्रथम' द्वारा जारी 'असर' रिपोर्ट में पाया गया कि पाँचवी कक्षा के बच्चे 2वी कक्षा की पुस्तक नही पढ़ पाए, और गणित के प्रश्न हल करने मे असमर्थ रहे।

शिक्षा के क्षेत्र मे सर्व शिक्षा अभियान, स्वयं, स्वयंप्रभा इत्यादि कार्यक्रमो के बावजूद भारत मे लर्निंग पॉवर्टी एवं क्षेत्रीय असमानताए देखने को मिलती है।

शिक्षा से संबंधित चुनौतियाँ

① शिक्षा संबंधित कार्यक्रमो एवं योजनाओं की असमान पहुँच। बिहार में 52% साक्षरता दर, केरल मे 90%

Don't write anything in this margin (इस स्थान में कुछ ना लिखें)

(c) शिक्षकों का प्रशिक्षण संबंधी सुधार की समस्या → शिक्षा का अधिकार, 2009 में शिक्षण प्रशिक्षण की बात नहीं

(d) सरकारी विद्यालयों का ढाँचा अत्यंत दयनीय; ब्लैकबोर्ड नहीं, कक्षा नहीं, शौचालय की कमी

(e) निर्धन एवं गरीब बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं।

बच्चों को विद्यालयों में अधिक आने के लिए प्रेरित करने हेतु 'मिड-डे मील' जैसी योजनाएं चालू की गई, किन्तु कोई मुख्य सुधार देखने को नहीं मिला।

महत्वपूर्ण सुधार किए जाने की आवश्यकता

- शिक्षा के अधिकार, अधिनियम 2009 में संशोधन की आवश्यकता।
- शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु 'निष्ठा' नामक कार्यक्रम
- नई शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों में समावेशी शिक्षा।
- लर्निंग पॉवर्टी को दूर करने हेतु 'निपुण' कार्यक्रम
- अन्य प्रयासों में ढांचागत सुधार, कम्प्यूटर, ऑनलाइन कार्यक्रमों हेतु उपकरण इत्यादि।

'पंचप्राणों' एवं 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने हेतु समावेशी शिक्षा एक 'उत्प्रेरक' की भांति कार्य करेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. In light of the burgeoning burden of both communicable and non-communicable diseases, there is a need to revamp the public health surveillance system in India. Discuss. (250 words) 15

संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों के बढ़ते बोझ के आलोक में, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत उच्चकोटिबद्धीय रोगो, संचारी एवं गैर- संचारी रोगो से प्रभावित देश है। भारत की लगभग 60 % जनता गैर संचारी रोगो के कारण मौत के घाट उतर जाती है।

संचारी रोग / संक्रामक रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को आसानी से फैलता है। प्रोटोजोआ, विषाणु एवं जीवाणु जनित रोगो को सम्मिलित किया जाता है। जैसे :- कोविड-19, चेचक, इबोला।

गैर-संचारी रोग से आनुवांशिक हृदय से संबंधित रोगो को शामिल किया जाता है। डायबिटीज, कैन्सर एवं हार्ट-अटैक।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की समस्याएँ
↓

- सिर्फ संक्रामक रोगों पर ही केन्द्रित गैर- संक्रामक रोगों की अवहेलना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अधिकता जबकि गैर- संक्रामक रोगों हेतु विशेषज्ञ तथा द्वितीयक एवं तृतीयक केन्द्रों की आवश्यकता।
- गैर- संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का आंकड़ा, संक्रामक रोगों से अधिक।
- डॉक्टर्स, अस्पतालों की कमी। भारत में 1500:1, 70% अस्पताल, 65% शहरों विद्यमान है। WHO के अनुसार 1000 पर 1 डॉक्टर होना जरूरी
- तकनीकी - प्रौद्योगिकी उपकरणों की कमी
- निगरानी प्रशासन की कमी (गाजियाबाद, गोरखपुर कांड)

Don't write anything in this margin
(इस क्षेत्र में कुछ भी न लिखें)

सार्वभौमिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार

- गैर-संक्रामक रोगों पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया जाना।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसमें संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों को सम्मिलित करना।
- डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत, जिसमें प्रत्येक नागरिक की रोग, इलाज संबंधित जानकारी हो।
- अवसंरचनात्मक सुधार, चिकित्सकों की भर्ती

उपर्युक्त सुधारों की सहायता से सतत विकास लक्ष्य-3 (स्वस्थ विश्व) की प्राप्ति में आसानी रहेगी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The repercussions of the ongoing economic crisis in Sri Lanka extend beyond its borders. Discuss with specific reference to India. Also, mention the steps that India has taken to assist Sri Lanka tide over the crisis.

(250 words) 15

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे भी पड़ रहा है। भारत के विशिष्ट संदर्भ में विवेचना कीजिए। साथ ही, उन कदमों का भी उल्लेख कीजिए जो भारत ने इस संकट से निपटने में श्रीलंका की सहायता के लिए उठाए हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप आपस में परस्पर संबंधित एवं जुड़े हुए है। एक भाग में भी अव्यवस्था संपूर्ण भाग को प्रभावित करती है।

श्रीलंका में जारी संकट

→ विदेशी मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा कोष की समाप्ति

→ आर्थिक संवृद्धि नकारात्मक

→ मुद्रास्फीति तथा तेल एवं मूलभूत आवश्यकताओं की कीमतों में वृद्धि

→ मुद्रा का अवमूल्यन

→ व्यापार का गिरना।

उपर्युक्त सभी समस्याओं के कारण भारत पर भी नकारात्मक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अवसर दिखने को मिल रहे हैं।

भारत पर प्रभाव

→ भारत- श्रीलंका के भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक संबंधों पर प्रभाव
→ श्रीलंका से शरणार्थी भारत की ओर आगमन कर रहे हैं।
→ श्रीलंका में रह रहे भारतीयों की आजीविका पर संकट
→ भारत- श्रीलंका के व्यापार में कमी (भारत, श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था)

भारत द्वारा उठाए गए कदम

→ श्रीलंका को मुद्रा आपूर्ति करने हेतु 'क्रेडिट ऑफ लाइन' एवं 'करेंसी स्वैप' के माध्यम से

सहायता।

→ मूलभूत आवश्यकताओं एवं कच्चे तेल की आपूर्ति करवाना

→ सस्ते ऋण की आपूर्ति सुनिश्चित करना

→ श्रीलंका के शरणार्थियों की सहायता प्रदान करना।

श्रीलंका- भारत के राजनीतिक साझेदारों में से एक माना जाता है। श्रीलंका के साथ भारत के रिश्तों को सुदृढ़ करने का यह महत्वपूर्ण समय है। संबंधों की सुदृढ़ता चीन को प्रतिसंतुलित करने में सहायक होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India is a reliable partner in the Indian Ocean Region and can take on the role of being the net security provider in the region. Discuss. (250 words) 15

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है और इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता होने की भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिए।

हिंद महासागर की रणनीतिक अवस्थिति एवं दक्षिण - पूर्व एशियाई देशों से जुड़े होने होने के कारण भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हिंद-महासागर की अवस्थिति

→ आसियान देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रवेश द्वार

→ आर्थिक महत्ता → मूल्यात्मक एवं मात्रात्मक रूप से क्रमशः 70% एवं 90% व्यापार हिंद महासागर से

→ अफ्रीकी देशों एवं मध्य एशिया को जाने में सहायक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत हिंद-महासागर में विश्वसनीय भागीदार

- भारत की महत्वपूर्ण समुद्री सीमाएँ हिन्द महासागर से जुड़ी हुई है।
- तटीय सुरक्षा बल एवं समुद्री रक्षा बलों द्वारा भारत हिंद महासागर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

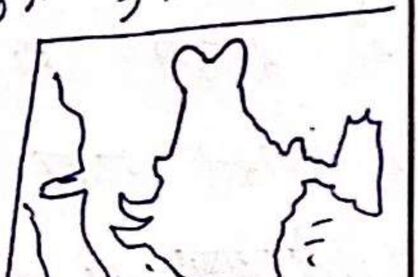

- भारत इण्डियन ओशन नेवल सिम्पोजियम (IONS), इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) का सदस्य

भारत का निवल सुरक्षा प्रदाता की भूमिका

- 1993 व 26/11 के मुंबई अटैक के बाद भारत ने हिंद महासागर में निगरानी को सुदृढ़ किया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(i) चीन की बढ़ती विस्तारवादी, डाइमण्ड चाल नीति, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (जिसमें हम्बनटोटा, चाबहार, CPEC, वन बेल्ट, वन रोड इत्यादि गतिविधियां को रोकने से सहायक)

(ii) भारत द्वारा ओमान से दुक्म इंडोनेशिया मे सबांग इत्यादि पोर्ट की सहायता से 'डायमंड नेकलेस' स्थापित कर रहा है।

हिंद महासागर की सुरक्षा से अफ्रीका - एशिया के संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। साथ ही द. पूर्व एशिया मे भारत एक रणनीतिक भूमिका को निर्वाहित करेगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)